

बढ़ावा देकर यदि उपनास्त्रा पर प्रातः जाय ।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 21 सितम्बर 2026 सोमवार

सम्पादकीय

अजीब मोड़ पर एआई

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार हँकिंग को जोखिम और मतभेदों के चलते एआई मॉडलों के वैश्विक विकास को धीमा करने के अग्रणी एआई डेवलपर्स की अपनी ही अपील को नजरअंदाज कर रही है, वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस तेजी से विकसित हो रही परिस्थिति पर भू-राजनीति द्वारा प्रतिक्रिया देने के लिए—तत्काली के बारे में एक वैश्वीयक नजरिया पेश कर रहा है। एआई कंपनियों और अमेरिका की सरकार ने लंबे समय से डेटा सेंट्रलों और उससे जुड़े निवेशों में लगाई जा रही भारी-भरकम रकम को अमेरिका और चीन के बीच की खाई में अपनी जमीन बचाए रखने के लिए अहम बताया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीकों और खनिजों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के खतर के बारे में आगाह किया। जबकि, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 'ब्रिक्स एआई' ओपन सोर्स कम्युनिटी की संभावनाओं पर जोर दिया, जो इस सेक्टर में किसी एक देश के दबदबे को चुनौती देनी। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है और इससे लार्ग करने की आवश्यकता को पूरी तरह बदल सकती है और इसे लागू करने की कार्ययत्न में शामिल होने से दीर्घकालिक अस्थि में फायदे भी हो सकते हैं।

फिर भी, 'ग्लोबल साइबर-कमी-कमी' खुद को बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता के बीच में फंसा हुआ पाता है। मसलन, यह एंप्रोपिकि के शक्तिशाली किस्सों और मिथकीय मॉडलों के चलते वैश्विक स्तर पर हो रही छटनी से पीड़ित है। व्यापारिक विवादों का असर आपसी भ्रूखला (सप्लाय चेन) पर पड़ने से एआई से जुड़ी क्षमताओं के विस्तार पर कौन असर न तो होना चाहिए और न ही पड़ने देना चाहिए, क्योंकि इन तकनीकों की वक्त पर आपस को सुलझात राहुदी युद्धा के लिए बेहद जरूरी है। यह उत्साहजनक है कि एआई से जुड़ी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त पहल, इस केंद्रिकरण का मुकाबला करने के वास्ते मंशाली ताकतों के बीच सहयोग के और रास्ते बना रही है। ओपन सोर्स और मिलकर काम करने के तरीके दुनिया के बाकी मुल्कों को एआई के मामले में अमेरिका की आक्रामक और अनिश्चितता नीति—निर्माण से बचा सकते हैं। भले ही ऐसे मॉडल अग्रणी निजी मॉलिकाना हक वाले (प्रोप्राइटी) मॉडलों की क्षमताओं को मुकाबले पीछे हैं, लेकिन वे तेजी से बेहतर हो रहे हैं। यह उन अर्धव्यवस्थाओं के लिए एक अच्छी बात है जहाँ एआई का विकास अभी बहुत उन्नत स्तर पर नहीं पहुँचा है, लेकिन वहाँ इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात खास तौर पर तब सच साबित होती है जब एआई सिस्टम निर्देशन न मानने और किसी काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जानें — यहाँ तक कि कमजोर सिस्टम को हैक करने — के संकेत दिखा रहे हैं। ऐसी क्षमताओं जिसे नियंत्रित करने वाले के हिसाब से बहुत ज्यादा या कम किया जा सकता है — का हथियार के तौर पर इस्तेमाल उन मुल्कों के लिए खिंता का सबब है निनकी साइबर सुरक्षा कमजोर है। ऐसे बदलते खतरों से निपटने वाली रक्षा क्षमताओं का विस्तार तभी संभव है जब तमाम मुक्त उन्हें बड़े पैमाने और कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करें। ब्रिक्स को ऐसा भी एक नमूना बनना चाहिए। एआई इतिहास की एक सबसे बड़ी अजमाजी बात को सामने लाते हैं जिन्हें बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन इनसे इंसानों को लोप जो खरते हैं उन्हें देखते हुए इसे एआई भू-राजनीति और ताकतवर व कमजोर के बीच मेघबाना वाले दांते में नहीं पड़ना चाहिए जो इस क्षेत्र में मौजूद कहरप्रियियों को साक्ष्य को दिशा देते हैं।

असहमति को मिले सम्मान

मनुष्य है सम्यता इसलिए नहीं बनाई कि सब एक जैसा सोचें। सम्यता का अर्थ है कि अलग-अलग सोच वाले लोग एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना साथ रह सकें। अगर सम्यता की इस लक्ष्य यात्रा के बावजूद सम्यता एक विफल प्रयास से मुक्त नहीं हो पाया है। वह है— अपनी बात को विचार और दूसरे की बात को समझा समझना। अपनी आवश्यकतित उसे स्वतंत्र चिंतन लगती है और दूसरे की आवश्यकतित अजड़ा। ईर्ष्या और द्वेष की जड़ें इसी मानसिकता में छिपी हैं। यानी हम जो कहें— वह तुम सुनो, तुम जो कहो— उसे सुनना हमारी जिम्मेदारी नहीं।

विडंबना यह है कि अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन में लोकल चाहते हैं, लेकिन अपने निजी संसार में मनमंजरी से काम करना चाहते हैं। राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन परिहार में नहीं। समाज में समानता चाहिए, पर अपने संबंधों में नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनें, लेकिन उनकी बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। दूरियाँ किसी एक बड़े विवाद से नहीं बनती। वे छोटे-छोटे अनुसूते वाक्यों से बनती हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने पूरा सुना बिना उत्तर दे दिया। किसी ने असहमति जताई और हमने उसके चरित्र का फैसला सुना दिया।

असली समस्या यह है कि हम सुनते हुए भी अपनी भीतर बोलते रहते हैं। सामने वाला वाक्य पूरा नहीं करता और हमारी भीतर उत्तर तैयार हो जाता है। हम उस उत्तर को नहीं सुन रहे होते, अपनी अकाली प्रतिक्रिया लिख रहे होते हैं। मनुष्य को अपनी बात सीधे सिद्ध करने में कई बार अधिक असम आता है। यह बहस जोखिम लेता है और मान लेता है कि संबंध ही जीत लिया। आपने कई बातें बहर में मिली विजय, संबंध में मिली पराजय होती है। आपने तर्क जीत लिया, लेकिन सामने वाले मन खो दिया। यही से ईर्ष्या का दूसरा चेहरा सामने आता है। जब हम दूसरे की याँयत्ता स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसकी उपलब्धि हमें अपनी कामी का अलगाव लगती है। वह अगर बढ़ता है और उसमें लगता है कि हमारा स्थान पीछे हो गया।

ईर्ष्या का सुविधाजनक रास्ता है उपलब्धि की व्याख्या बदल देना। मेहनत को माय्य कह दीजिए, प्रतिभा को संयोग, उपलब्धि को सफ़ाईशर और सफलता को कृपा कह दें। इससे आत्मसमन सुखित रहता है। अगर असहमति पास पड़ेगा है कि यदि सामने वाला समुच्चय आपका है, तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। द्वेष डूबी मानसिक सुविधा का आलाप करण है। ईर्ष्या पूछती है, इसके पास क्यों? द्वेष कहता है, इसके पास नहीं होना चाहिए। फिर व्यक्ति दूसरे को गिराने में सही सोझा खोजने लगता है, जो उसे स्वयं कुछ उचित उसे मित्रता चाहिए था। विडंबना यह है कि वह दूर की सफलता हमें प्रेरित करती है और पास की सफलता परेशान। किसी अनजान व्यक्ति की उपलब्धि पर हम कहते हैं, देश का मन रोशन कर रहा है। वही उपलब्धि पड़ोसी शहरिल कर ले, तो भीतर का आलोकच जग जाता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। परिहार है यही मनोविज्ञान रिस्ती को पीत से खोखला करता है। सहमति में साथ चलना सुविधा है, असहमति में साथ रहना सम्यता।

विधानसभा चुनाव: डेमेज कण्ट्रोल में जुटी भाजपा और मुद्दे

—अशोक भाटिया—

लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपनी उच्छा और अति-पिछड़ी के आखण के मुद्दे को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर रहे निषाध पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाध को मनाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रमारी विनोद तावड़े खुद उनके आवास पर पहुँचे।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में साल 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो चुका है, जिसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अजेय मानी जाने वाली छवि को गहरा धक्का पहुँचाया। दिल्ली की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काजिज होने के बावजूद, देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी की सीटों का आंकड़ा लगभग आधा रह जाना एक ऐसी चेतावनी थी, जिसे नजरअंदाज करना आत्मतप्ली साबित हो सकता था। इस चुनौती झटके के जहाँ एक ओर समाजवादी पार्टी और अनिवार्य शर्त बन चुकी है।

सा गठनिक कसावट के साथ—सच्चा भाजपा का यह डैमैज कंट्रोल केवल पार्टी केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहयोगियों और प्रमुख चेहरों को जोड़े रखने के लिए एक आक्रामक राजनीतिक बेराबदी में बदल चुका है। इसी कड़ी में हाल ही दो बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं, जो भाजपा की इस गंभीर रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। पहला घटनाक्रम रायबरेली सत्रर से भाजपा विधायक अदिति सिंह का है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में अदिति सिंह की काग्रेस में संभावित वापसी को लेकर तरह-तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रही थे। इन अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए और विश्वास के मनोबल को तोड़ने के लिए अदिति



प्रयास कर रही है।यदि 2027 में प्रमुख चेहरों को जोड़े रखने के लिए एक आक्रामक राजनीतिक बेराबदी में बदल चुका है। इसी कड़ी में हाल ही दो बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं, जो भाजपा की इस गंभीर रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। पहला घटनाक्रम रायबरेली सत्रर से भाजपा विधायक अदिति सिंह का है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में अदिति सिंह की काग्रेस में संभावित वापसी को लेकर तरह-तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रही थे। इन अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए और विश्वास के मनोबल को तोड़ने के लिए अदिति

सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक मुश्किल मुलाकात की। इस बेकन ने न केवल सीन अफवाहों पर पूरी तरह विदाग फार दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया, कि रायबरेली जैसे गांधी परिवार के पारंपरिक गढ़ में भाजपा अपने किले को अमेज रखने के लिए पूरी तरह मुस्तेद है।

इसी रणनीति का दूसरा और ओहो महत्वपूर्ण हिस्सा अपने नाजख सहयोगियों को संमालना है, जिसमें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई करन नहीं छोड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपनी उपेक्षा और अति-पिछड़ी के आखण के मुद्दे को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर रहे निषाध पार्टी के अ

ध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाध को मनाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रमारी विनोद तावड़े खुद उनके आवास पर पहुँचे। दोनों नेताओं के लिए यह इस मौकाम का मुख्य उद्देश्य सहयोगी दलों के भीतर पनर रहे असंतोष को समर रहते दाना और 2027 से पहले एनडीए के कुनबे को पूरी तरह एकजुट रखना

यूपीआई: बोझ तो ग्राहक ही उठारेंगे..?

—अभिभव नाथ—



करोड़ों यूपीआई यूजरर्स के मन में एक सवाल पुनर रहा है। सवाल ये कि क्या 2000 रुपए से ऊपर की यूपीआई पेंमेंट पर आपको पैसा देना होगा? मतलब आप ५५00 की यूपीआई करोगें तो मुक्त और ५५000 की करोगें तो क्या आपकी जेब से कुछ कटेगा? और अगर कटेगा तो फिर जिस डिजिटल इंडिया का नाम लेकर सरकार ने खुद कहा था कि यूपीआई श्री करेगा। उसी सरकार के अपने कागज में कल पहली बार 2000 को लेकर एक लकीर क्यों खींची? उसी कागज में एक तरफ लिखा था कि बैंक 2000 तक की पेंमेंट पर ध नहीं ले सकते। ना सिधे ना धुमाकर। लेकिन दूसरी तरफ 2000 के ऊपर कुछ कड़ीशर लगाई गई थी। वो कड़ीशर क्या पैसा लेने के लिए? सवाल यह भी उठता है कि जो लकीर आज तक कहीं थी नहीं उसे सरकार क्यों लगा रही है?

य्ा यूपीआई को लेकर जो नप नियम हैं वो सिर्फ कागजों के फेरवेलर है या वाकई में 2000 के ऊपर चार्ज लगेंगे और चार्ज लग रहा है तो किसकी जेब से कटेगा? आम आदमी की जेब से या वो जो इसे बिचनेस में इस्तेमाल करते हैं दुकानदार उनकी जेब से और अगर दुकानदार की जेब से भी जाता है तो क्या वो धुमकर आपके सामने हैं वो नहीं डूकेन? यूपीआई से लोग आज शहर से भी पैसा भेजते हैं। स्कूल की फीस जमा करते हैं। हर महीने घर का राशन ऑनलाइन हमारे हाथ में आता है। आपने तर्क जीत लिया, लेकिन सामने वाले भी लोग जो हैं वो यूपीआई दिखाते हैं। तो जो सबक मन में ये सलान है कि माई साहब 2000 के ऊपर अगर 3000 का बिल गया तो क्या पैसा लेला? 4000 डॉलर की फीस मांगा तो क्या फीस के साथ यूपीआई का भी टैक्स देंगे? और घर का किराया तो 8000, 10000 2000 हो तो क्या वहां जाएगा?

15 सितंबर को खबरों में खबर आ गई कि यूपीआई पर 2000 के यूपीआई ट्रांज़ेक्शन पर कोई पैसा नहीं लगेगा। खबको समझ में आ गया कि यार 2000 के ऊपर वाले तो तो लगेगा ही लगेगा। सरकार अगर यह कर रही है तो कोई बहान दिन से ही चल रहा था कि यूपीआई ट्रांज़ेक्शन पर सरकार चार्ज लगाने वाली है। कई बार खंडन होता, कभी यह लिर्फ दुकान पर होने वाले पेंमेंट की बात है। दोस्त या घर वाले को बड़ी पैसे भेजने पर चाहे जितनी बड़ी कमी हो पैसा नहीं जाएगा। हा और अभी तक वह फीस लगाने का कोई अतिम फैसला नहीं हुआ है कि दुकानदार पर किन्ती लेनी यह एप्लीसीआई की एक कमेटी दूर करेगी। यानी वही सरकारी कंपनी जो यूपीआई को पीछे पचाती है और जिसका काम अभी शुरू हुआ है। इसे भी पड़ेरु दुकाने इस्तरायल को झटका है। क्या भारत ने बदल लिया अपना रुख, ईरान के लिए नेतरेव्याह को छोड़ा? आम लोगो पर शुल्क लगेगा? नहीं, यूपीआई भुगतान मुक्त रहेगा। चाहे भुतान Person&to& Person (P2P) हो या अक्वेर-उज-अक्वेरव्याह (P2M) ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाएगा। UPI पर ग्राहक से कोई फीस नहीं लेगे। QR स्कैन करने पर चार्ज लगेगा? नहीं। छोटे भुगतान के ली के तरह मुक्त रहेंगे और व्यापारी वह शुल्क ग्राहक से ही वसूलेंगे। सरकार के मुताबिक, बैंक व्यापारियों के लेन-देन पर नजर रखेंगे। छोटे व्यापारी 2,000 से अधिक के भुगतान पर क्या होगा? ऐसे भुगतान पर 0.40 शुल्क लागू होगा। हालाँकि, अगर व्यापारी की UPI से किसी भी प्रप्री 1 लाख तक है, तो MDR नहीं लगेगा। क्या नया QR कोड लेना होगा? नहीं। मौजूदा QR कोड से ही भुगतान जारी रहेगा। क्या जीएनटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? नहीं। शुल्क MDR का लक्ष्य लेने के लिए GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। सीमा कैसे तय होगी? बैंक व्यापारी के लेन-देन की निगरानी करेंगे। अगर लमालम 3 महीने तक UPI से प्रप्री 1 लाख से अधिक रहती है, तभी व्यापारी को Person &to& Merchant नहीं बदल जाएगा। बड़े व्यापारी ईई कॉमर्स

2,000 से कम के भुगतान पर भी जीरो MDR लागू है। वहीं, 75,000 से अधिक के लेनदेन के लिए एंडी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के मुकाबले UPI किताबत फिकायती रहे? अभी कोडिफ़ेड कार्ड पर 1.5 से 2.5 और डेबिट कार्ड पर 0.90 तक शुल्क लगता है। इसके मुकाबले UPI पर सिर्फ 0.40 या अधिकतम 300 पर शुल्क रहेगा।

कूटनीति के बीच उलझा काली नदी का स्रोत



जय सिंह रावत

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत–नेपाल सीमा के उस विवाद को फिर उठाया है, जिसकी जड़ें 1816 की सुगौली संधि हैं। और उसके बाद हुए ब्रिटिश संधियों तक जाती हैं। खानल ने 15 सितंबर को नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कहा कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधरा को नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में शामिल करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है।

इस विवाद की कुंजी दो सौ साल पुराने एक सवाल में छिपी है सुगौली संधि में जिस 'काली नदी' को सीमा माना गया, उसका वास्तविक उद्गम कहाँ है? नेपाल लिम्पियाधरा की ओर से आने वाली लंबी और अधिक जलसमृद्ध की कुटी–यांगती को काली या महाकाली की मूल धारा मानता है, जबकि भारत की ऐतिहासिक–प्रशासनिक स्थिति कालापानी क्षेत्र को उत्तरखंड के पिछोरगंग जिले का हिस्सा मानी रही है। इसलिए यह जमीन से पहले नदी की पहचान का विवाद है।

1814–16 के आंग्ल–नेपाल युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के अन्तर्द्व पांच न न काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा का आधार बनाया। लेकिन सन् 19५१ के आंग्ल–नेपाल संधि के अन्तर्द्व उपमग को स्पष्ट निर्देशकों से परिभाषित नहीं किया। कंटेन विलियम डे. वेब ने 1815 से 1821 के बीच कुमाऊ का सर्वेक्षण किया। सन् 1816 तक काली के ऊपरी स्रोतों तक पहुँच चुका था। कालापानी के झरने उसके शुष्कतम क्षेत्रवर्षा में महत्वपूर्ण भौगोलिक चिह्न के रूप में दर्ज हुए।

वर् 1817 में ही यह विवाद ब्रिटिश भारतीय प्रशासन और नेपाल दरबार के सामने आ गया था। नेपाल के दावे की जांच के बाद काली के पूर्व में स्थित कितरि और छांगर क्षेत्र नेपाल को सौंप दिए गए। इसके

कार्यक्रमों में बड़–चड़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इसके समानांतर, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और राज्य में आ रहे भारी–भरकम औद्योगिक निवेश के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के दावों को सोशल मीडिया और जमीनी अभियानों के माध्यम से जनता के बीच ले जाना जा रहा है। विश्वास द्वारा महंगाई और बेरोजगारी पर बनाए जा रहे माहौल का मुकाबला करने के लिए भाजपा अपनी 'डाल डाल' सरकार के विकास कार्यों जैसे एक्सपेसवे का जाल, हवाई अड्डों का विकास और बेहतर कानून–व्यवस्था को मुख्य डाल बना रही है।

एक और महत्वपूर्ण मोर्चा जिस पर भाजपा बहुत बारोकी से काम कर रही है, वह है टिकट वितरण और एंटी–इक्वेसिटी का प्रबलन। पार्टी के आंतरिक सूत्रों और स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का गहन और बहुस्तरीय जमीनी सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में न केवल विधायकों की लोकप्रियता और उनके कामकाज का आकलन किया जा रहा है, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि और कार्यन्तर्ताओं के साथ उनके व्यवहार के भी मापा जा रहा है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सत्ता विरोधी लहर को काटने और जनता के मुस्ते के शान्त करने के लिए भाजपा 2027 के चुनावों में 30 से 40 प्रतिशत मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है या उनके क्षेत्र बदल सकती है। नए युवा और स्थानीय स्तर पर सकीयर्ष चेहरों को मौका देकर पार्टी एक 'नया और ऊर्जावान' विकल्प पेश करने की तैयारी में है, जिससे गणतंत्र के खरों को कम से कम किया जा सके।

आजमगढ़, अयोध्या, सहानपुर और मुरादाबाद जैसे मंडलों की हारी हुई सीटों और विशेषकर उन 16 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहाँ पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब था, और इन क्षेत्रों की कमान सीधे वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों को सौंप दी गई है।

अंततः, उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव केवल देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह 2029 के अगले लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेगा। भाजपा भली–भांति जानती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है और रुपी में किसी भी प्रकार की शिथिलता उसके राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभुत्व को संकट में डाल सकती है। वर्तमान में काजपा द्वारा किए जा रहे डैमैज कंट्रोल के प्रयासकुवाहे यह अदिति सिंह की मुख्यमंत्री से मुनाबत हो या निषिध काटका का संजय निषाध को घर पहुँचानाकवाह दर्शाते हैं कि पार्टी अपनी पराजय को स्वीकार कर आत्मसंतुष्टि के जाल से बाहर निकल चुकी है और एक अनुप्राणित सेना की तरह अपने कमियों को सुनाने में जुट गई है। विश्वास के सामाजिक नैरेटिव को तोड़ना, कांफ़ेसिटी को दोबारा स्तब्ध करना, सहयोगियों को संकष्ट रचना और सुशासन के दावों पर जनता का विश्वास बहाल करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन चुनावी राजनीति के माहिर विश्लेषकों के रूप में भाजपा ने जिस तरफ से माइको–कंट्रोले और सामाजिक संकरणों को नए सिरे से गढ़ने का कूट्मिट तैयार किया है, उसने 2027 की लड़ाई को बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। आगामी महीनों में यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की यह नई विस्तार विषय के बंदे होसलें को किसत किसके में कितनी कारगर साबित होती है।



बाद नेपाल ने पश्चिम की ओर दवाा बढाते हुए काली कि कुटी घाटी से आने वाली कुटी–यांगती को काली की मुख्य धारा माना जाना चाहिए। बाद में 'हिलियमन कालोटेर' में दर्ज विवरण के अनुसार वेव और अन्य आधिकारियों का मत था कि कालापानी के पवित्र स्रोत से निकलने वाली अंधाकाली नदी नेपाल की परंपरागत रूप से काली की मुख्य धारा माना जाता था और उसी नदी को उसका नाम दिया।

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 5 सितंबर 1817 का तत्कालीन सरकारी निर्णय है। कुमाऊँ के कमिश्नर जी. डब्ल्यू. ट्रेल को भेजे गए आदेश में गवर्नर–जनरल लॉर्ड मोइरा की सरकार ने नेपाल के कुटी और नाबी संसदीय दायों को स्वीकार नहीं किया। कालापानी नाम की धारा को काली की प्रमुख शाखा और दोनों राज्यों के बीचा सीमा मानने की व्याख्या की गई। इस प्रकार सुगौली संधि के तत्काल बाद ही विवाद की जड़ें हुईं और कुटी–नाबी पर नेपाल का विस्तारित दावा अस्वीकार कर दिया गया।

नेपाल उन्नीसवीं सदी के कुछ ब्रिटिश मानचित्रों को अपने ध्यान में रखकर मानता है। कुछ शुष्कवाती क्षेत्रों में लिम्पियाधरा से आने वाली पश्चिमी काली दिखायी जा रही है। लिपुलेख सडियों से हिमायार पात्र व्यापार का मार्ग रहा है और आज कैलास–मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण रास्ता है। दिखार्इ देते लगता है। ही यह विवाद का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। 1817 का प्रशासनिक पत्राचार भारत के शासनाधिकार और लिपुलेख क्षेत्र को उसमें प्रस्तुत करता है, जबकि कुछ ब्रिटिश मानचित्र नेपाल को अपने दावे के लिए आधार देते हैं।

नेपाल का दूसरा प्रमुख तर्क ओर अस्वीकार किया है।

— लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

3

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंशना एव श्रवगत नाम से हुआ। इसका बाद स्वरंग ने राधा कान्हेर की प्रस्तुति की। तत्पश्चात् मिश्र ने राधाय मनमोहक गायक सबका मन मोह लिया। इसका बाद निदेश, स्वरंग, अर्चना, अनिकेत अण्णा, स्वरंग, सुश्री, ना. वि. खिख अंजली ने राधा मल्हारी की प्रस्तुति दी। संस्थान के होनहार छात्र प्रथम मिश्रा ने बांगुरी वादन कर वाह वाही लुट्टी बच्चों द्वारा कजरगी गीत की भी प्रस्तुति दी गई। अण्णा के द्वारा भीरु की प्रस्तुति दी गई। साथ ही साथ संस्थान के बच्चों ने कव्याली की अनोखी प्रस्तुति देकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में कीर्लोड पर र. धिप, पर पंकज गुप्ता, लोकक पर अणिकेत आर्य ने अपनी संपात से कार्यक्रम में चार चंदन अर्थात्, इस अवसर पर अभिषेक संन, प्रमोद आर्जि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रबन्धक विनोद उपाध्याय ने किया।

नरसिंहा बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व.
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
 स्वीकृतिकाश्री, प्रकाशक, मुद्रक
 प्रतीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण
 लिटिंग प्रेस जि. नयाहाल
 1-4 A लोहिया काम्पलेक्स
 जिन्दा चंचायात भवन गान्धीनगर
 बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं
 प्रकाशित।
 प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह
 संयुक्त सम्पादक-**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
 अधीन-फैजाबाद कार्यालय-
 चतुर्थी नदि परिसर लक्ष्मण घाट
 अधीन-फैजाबाद
 लक्ष्मण कार्यालय-
 अखिलाना चौहाल, एन.डी.ए. कालोनी,
 रोहतास एच. कानपुर से लक्ष्मण।
गोरेखपुर कार्यालय-
 इलाहाबाद गोरेखपुर।
 मो. 9336715406, 8400925463
 ईमेल**bhartiyaabasti@gmail.com**
 ईमेल**bhartiyaabasti@gmail.com**